एफ०डी०आई० इन रिटेल - वरदान या अभिशाप ?

राजेन्द्र गाबा
चैप्टर चेयरमैन,सहारनपुर

पहले तो हमें यह जानना चाहिये कि किसी क्षेत्र में एफडीआई की जरूरत क्यों होती है। एफडीआई से जहाँ उपभोक्ता को तो फायदा होता ही है, वहीं बुनियादी ढ़ाँचे एवं अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है। देश में टूरसंचार, वाहन और बीमा क्षेत्र में एफडीआई की वजह से आई कामयाबी को हम देख ही चुके है। इन क्षेत्रों में बडे पैमाने पर हुए निवेश की वजह से ग्राहकों को बेहतर सेवाऐं एवं उत्पाद नसीब हुए हैं। बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा में भी कंपनियों को खुद को बेहतर बनाने के लिये प्रेरित किया है।

कहा जा रहा है कि एफडीआई से छोटे कारोबारों को नुकसान होगा और उनकी आजीविका संकट में पड़ जायेगी। एफडीआई का सबसे बड़ा लाभ है कि भारत दुनिया का शॉपिंग हब बन सकता है, इससे अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। उदाहरण के तौर पर कम्पयूटराइजेशन के समय भी देश भर में विरोध हुआ था, लेकिन आज वही कम्पयूटर हर एक की जरूरत बन गया है। रिलायंस जैसी देश की बड़ी कम्पनी ने उपभोक्ता बाजार में घुसपैठ की थी तो उसका भी विरोध हुआ था। लेकिन आज बाजार में कहीं उसका असर नज़र नहीं आता। इन दोनों ने देश को लाखों रोज़गार उपलब्ध कराये हैं।

एफ०डी०आई० इन रिटेल के आने पर एम.एस.एम.ई. के सामने नई चुनौतिया आयेंगी। मेरे विचार से रिटेल मार्केटिंग के लिए विदेशी कम्पनियों द्वारा गुणवत्तायुक्त एवं सस्ती जो प्रतिस्पर्धा में टिक सके, का क्रय कर रिटेल मार्केटिंग की जायेगी। एम.एस.एम.ई. सेक्टर कारपोरेट ग्रुप से तभी टक्कर ले सकता है जब सरकार द्वारा एम.एस.एम.ई. के हित में प्रोत्साहन देने के लिए उसे मध्यम एवं वृहद उद्योगों की अपेक्षा कम दर पर बिजली, ग्रह कर की माफी, सस्ती ब्याजदर पर ऋण, वाणिज्य कर में छूट एवं नये पूंजी विनियोजन पर उपादान देने की योजना बनाई जायें। आज के आधुनिक दौर में टैक्नोलॉजी अपग्रेडशन के लिए आधुनिक मशीनें एवं उन पर उपादान, टैक्नीकल ट्रेनिंग की व्यवस्था कर आधुनिक टैक्नोलॉजी पर प्रशिक्षण दिलाना, विदेशों में उद्यमियों को भेज कर नई टैक्नोलॉजी का ज्ञान कराना तथा उसे आयात कराना, फूड एंड सेफ्टी एक्ट के प्रकार के एक्ट की जानकारी हेतु उद्योगों के लिए कार्यशाला आयोजित कर उद्यमियों का ज्ञान वर्धन करना आदि इन सभी प्रयासों से लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के उत्पादों की गुणवत्ता तो बढ़ेगी ही साथ-साथ उत्पादन लागत कम होने की सम्भावना होगी, जो बडे उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में एफ.डी.आई. के रिटेल मार्केट में खडे हो सकेगें। मेरे विचार से आगामी ५ वर्षों में इससे १० बिलियन डॉलर की राशि अपने देश में आयेगी जो देश की अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने का काम करेगी तथा देश का विकास होगा।

रिटेल में एफडीआई के समर्थन में दिये जाने वाले तर्क-

☑ एफडीआई से अगले तीस साल में रिटेल में एक करोड़ नई नौकरियाँ मिलेगी :- माना जा रहा है कि इस कदम से पूरे देश में सामान की कीमतों में एकरूपता आयेगी। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि लाखों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को अलग तरह का प्रशिक्षण मिलेगा और उनके लिये संभावनाओं के नये द्वार खुलेंगें।

☑ बिचौलियों का होगा खात्मा- एफडीआई का सर्वाधिक फायदा यह होगा कि काला बाजारियों, मिलावटखोरियों और बिचौलियों पर रोक लगेगी। बिचौलिये खत्म हो जायेगें, बीच में कमीशन खाने वालों की छुट्टी हो जायेगी, जिससे उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर सामान मिलेगा। किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और अपने सामान की सही कीमत भी। जानकारों का मानना है कि एफडीआई के आने से विदेशी कंपनियों को कम से कम तीस प्रतिशत कच्चा माल भारतीय किसानों से ही खरीदना होगा, जिससे किसानों की स्थिति सुधरेगी। कच्चा उत्पाद किसान के पास से सीधा कंपनी के पास पहुँचेगा, इससे किसानों और कंपनी दानों को उचित लाभ मिलेगा, मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से किसानों को फायदे का लंबी अवधि में विश्लेशण करने की जरूरत है। अगर देश के छोटे किसानों और दस्तकारों तक इसका लाभ पहुँचे तो यह कदम फायदेमंद साबित होगा, मांग बढ़ेगी तो कृशि क्षेत्र में भी सुधार होगा।

☑ कंज्यूमर को क्या फायदा- लोगों को कम दामों पर विश्व स्तर की चीजें उपलब्ध होंगी।

☑ छोटे दुकानदारों को नुकसान या फायदा:- छोटे दुकानदार को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बड़ी कंपनियों और छोटे दुकानदारों के करोबार करने का तरीका अलग-अलग है। बड़े शहरों में ही खुलेगी संगठित क्षेत्र की शॉप्स। सस्ता मिलेगा छोटे दुकानदारों को सामान।

☑ रूपये की हालत सुधरेगी :- निवेश आने से रूपये की खस्ता हालत में भी सुधार होगा कुल मिलकर सरकार के इस फैसले से रिटेल की दुनिया में सकारात्मक क्रांति आने की उम्मीद है निश्चित ही देश के लिये ये एक फायदे का सौदा साबित होगा। एफडीआई से विदेशी निवेशक और निवेश हासिल करने वाला देश दोनों को फायदा होता है। निवेशक को यह नये बाजार में प्रवेश करने और मुनाफा कमाने का मौका देता है।

☑ रिटेल में एफडीआई से लोगों को कम दामों पर मिलेगा बेहतर सामान:- शर्त के अनुसार विदेशी कंपनियाँ कम से कम ३० फीसदी सामान भारतीय बाजार से ही लेगी। इससे देश में नई तकनीक आएगी एवं लोगों में आय बढ़ेगी और औद्योगिक विकास दर में भी सुधार होगा।

☑ विदेशी कंपनियाँ सप्लाई चेन सुधारेंगी तो खाद्य सामग्री का खराब होना थमेगा।

☑ सामान कम खराब होगा तो इससे खाद्य महंगाई भी सुधरेगी।

☑ इतना ही नहीं फल, सब्जी व आनाज के भण्डारण में भी करोडों की पूंजी का विनियोजन एफ.डी.आई. के माध्यम से होगा।

☑ रिटेल स्टोर और हॉट बाजार या छोटी दुकानें एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करेगी।

देश की बड़ी कंपनियों को पहले ही रिटेल में आने की स्वीकृती प्रदान की है। चीन या फिर इंडोनेशिया, जहाँ भी रिटेल में एफडीआई को मंजूरी दी गई है वहाँ एग्रो प्रोसेसिंग इन्डस्ट्रीज को बहुत लाभ हुआ है।

अत: मेरे विचार से सरकार द्वारा एम.एस.एम.ई. के हित में न्यायोचित निर्णय लेने से नीति अनुकूल हो सकती है। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमें एफडीआई इन रिटेल को स्वीकार करना चाहिये।▲